THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MOHD. AYUB KHAN): Yes Sir. The Ministry of Agriculture through 1he Indian Council of Agricultural Research is pursuing and strengthening its research efforts for developing suitable scientific methods of cultivation for improving input efficiencies and increased productivity per unit area for small and marginal land holdings.

The technologies include adoption of improved crop varieties (seed), timely planting, scientific water management, plant protection practices and integrated nutrient management etc.

खेल परियोजना विकास क्षेत्र (एस.पी.डी.ए.) योजना के अंतर्गत खेल-कूद केन्द्रों की स्थापना

1202. **श्री दिलीप सिंह जूदेव**: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार "खेल परियोजना विकास क्षेत्र" योजना के अंतर्गत खेलकूद केन्द्रों की स्थापना हेतु राज्यों को कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करा रही हैं;

(ख) ऐसे केन्द्रों की स्थापना करने हेतु राज्य-वार कितने-कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) अब तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी हैं;और

(घ) राज्य-वार कितने-कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं और इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान करने की संभावना हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): (क) केन्द्रीय सरकार,अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा मैदानी क्षेत्रों में और 75 प्रतिशत हिस्सा पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में प्रदान करती हैं । विभिन्न राज्यों में एस.पी.डी.ए.केन्द्रों की स्थापना के लिए स्वीकार्य केन्द्रीय सहायता की अधिकतम धनराशि मैदानी क्षेत्रों के लिए 75.00 लाख रूपये हैं । भारतीय खेल प्राधिकरण,राज्य में सृजित की गई खेल संबंधी बुनियादी सुविधाओं का मूल्यांकन करने के पश्चात् का धनराशि का निर्धारण करता हैं ।

(ख) और (ग) राज्य-वार प्राप्त प्रस्तावों की संख्या और एस.पी.डी.ए.केन्द्रों के लिए अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या संलग्र विवरण में दी गई हैं । (**नीचे देखिए**)

(घ) इस विभाग में कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं ।

विवरण

खेल परियोजना विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र के नाम	एस.पी.डी.ए.के लिए प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	3
2.	असम	1	1
3.	अरूणाचल प्रदेश	1	1
4.	बिहार	3	3
5.	गोवा	1	1
6.	गुजरात	3	3
7.	हरियाणा	1	1
8.	हिमाचल प्रदेश	1	1
9.	जम्मू व कश्मीर	1	1
10.	कर्नाटक	2	2
11.	केरल	2	2
12.	मध्य प्रदेश	5	5
13.	महाराष्ट्र	4	4
14.	नागालैंण्ड	1	1
15.	उड़ीसा	2	2
16.	पंजाब	2	2
17.	राजस्थान	3	3
18.	तमिलनाडु	2	2
19.	उत्तर प्रदेश	3	3
20.	पश्चिम बंगाल	2	2
21.	चंडीगढ़	1	1
22.	मेघालय	1	1